पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 23, अंक 4/2022

'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान के तहत राज्य स्तरीय परिचर्चा आयोजित

शेयरिंग की भावना को बढ़ाने के साथ ही जागरूकता के लिए महिलाओं को आगे आना होगा

'हमारे समाज में शेयरिंग की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए जागरूकता लाने के साथ-साथ महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि महिलाएं ही समाज में बदलाव ला सकती है।' उक्त विचार 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक, राजस्थान' के अन्तर्गत आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर ने व्यक्त किए।

उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान बताया कि जिस कचरे को हम कचरा समझते हैं उसी में से 'कबाड़ से जुगाड़' के माध्यम से 'कट्स' और इनकी सहयोगी संस्थाओं ने इतने अच्छे उत्पाद बनाए हैं, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमें अपने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि 'ग्रीन एक्शन वीक' प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह अन्तरराष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जो कि सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीडन के सहयोग से वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाता है।

इस अवसर पर 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'कट्स' द्वारा इस अभियान को राजस्थान के अलावा भारत के 14 अलग-अलग राज्यों में भी संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अभियान का मुख्य मुद्दा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूषण है, जिसको कि भारत सरकार ने भी जुलाई 2022 से पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया है।

हमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए सतत् उपभोग को बढ़ावा देना होगा। राजस्थान में जल एवं वन संपदा बहुत ही सीमित मात्रा में है, जिसका उपयोग आमजन को बेहतर तरीके से करना चाहिए।

कार्यक्रम में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के सदस्य सचिव के.सी.मीणा ने बताया कि उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, हमें इसे घटाने की जरूरत है। उन्होंने साइक्लिंग के कल्चर को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 'सादा जीवन उच्च विचार की जीवन शैली अपनाकर हम प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सीमित कर सकते हैं।

कार्यक्रम में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के रीजनल ऑफीसर विजय शर्मा ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए आमजन को जागरूक होना होगा। उन्होंने ई-वेस्ट का सही तरीके से रीसाईकल करने पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को भी स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व को समझना होगा।

राजस्थान विश्व विद्यालय की होम साईंस विभाग की प्रोफेसर डॉ. निमाली सिंह ने बताया कि गांवों में आज भी वस्तुओं और सेवाओं को साझा करने की प्रवृत्ति है, इसे शहरी क्षेत्रों में भी फिर से बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करना होगा। इस अवसर पर किचन गार्डन, 'कबाड़ से जुगाड़' प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।

'ग्रीन एक्शन वीक' अभियान की कार्यक्रम अधिकारी निमिषा शर्मा ने अभियान के तहत अब तक की गई गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अंक में...

- प्रदेश में बढ़े अपराध 3
- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई जलवायु 5
- भारत संभालेगा अब जी-20 की कमान 6
- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला . 7
- पूरा बजट कभी काम ही नहीं आता 10

शहरी निकायों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम

सामुदायिक भागीदारी शहरी सुशासन के लिए आवश्यक

शहरी निकायों के सुशासन व क्षमतावर्धन के लिए वित्तीय प्रबंधन और लोगों की भागीदारी से कार्य करने पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यह विचार 'कट्स' द्वारा 22 दिसम्बर 2022 को कोटा में राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग तथा ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित शहरी निकायों का क्षमतावर्धन कार्यक्रम में कोटा नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत ने मुख्य अतिथि के रूप में रखे। उन्होंने कहा विभागों में अलग-अलग सोच होने से कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है। सोच में समग्रता से ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

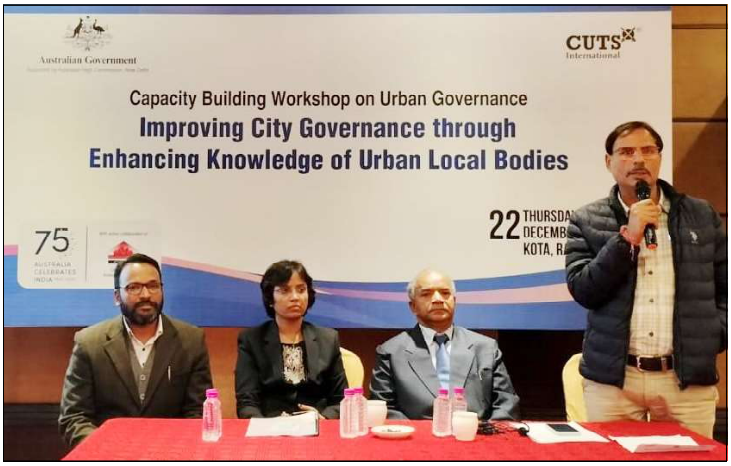

इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के संभागीय उप-निदेशक दीप्ति रामचन्द्रन ने निकायों के वित्तीय प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सतत् परिवहन और सामुदायिक भागीदारी विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्षमता वर्धन कार्यक्रम में नवाचारों को भी शामिल करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से कार्यक्षमता बढ़ती है और प्रशासन में सुधार आता है। कार्यक्रम में हैदराबाद ग्रेटर मुन्सिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एक्जिक्यूटिव इंजीनियर डॉ. सुधाकर दच्चिपल्ली मुख्य प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अमर दीप सिंह ने बताया कि विगत एक दशक से शहरी सुशासन और शहरी निकायों के क्षमतावर्धन के लिए 'कट्स' द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के साथ एक सहमति पत्र के तहत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के क्षमतावर्धन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों के ज्ञानवर्धन के द्वारा आम नागरिकों की जीवन शैली में सुधार करना है। कार्यक्रम में कोटा संभाग के 30 निकायों के अधिकारियों ने भाग लिया।

पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं कर सकती हैं बचत

यदि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पांच क्यारी में पोषण वाटिका लगाकर उसमें सब्जियां और फलदार पौधे लगाती हैं तो परिवार में सात हजार रूपए की बचत कर सकती हैं। साथ ही पूरे परिवार को वर्षभर ताजा और शुद्ध सब्जियां उपलब्ध होगी। जिससे परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उक्त विचार 'कट्स' के राजदीप पारीक ने डूंगरपुर जिले की खानन ग्राम पंचायत के नई बस्ती गांव में आयोजित पोषण वाटिका प्रशिक्षण के दौरान व्यक्त किए।

ग्रामीण विकास संस्थान के हरिराम लबाना ने बताया कि 'कट्स' एवं स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन के सहयोग से प्रोस्कोप परियोजना राजस्थान के 12 जिलों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में मॉडल जैविक गांव बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। कार्यशााला के दौरान लबाना ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि पोषण वाटिका प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक ग्राम बनाने की दिशा में सभी घरों में पोषण वाटिका विकसित करवाई जाएगी।

कृषि पर्यवेक्षक किशोर कुमार, ने किसानों को जैविक खेती के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कीट प्रबन्धन, रोग प्रबन्धन, पोषण प्रबन्धन आदि के बारे में जानकारी दी । कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरपंच लाल शंकर ने सभी प्रतिभागियों को जैविक खेती अपनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सब्जियां की पौध तैयार करने एवं पोषण वाटिका की रूपरेखा बनाने का प्रदर्शन भी किया गया तथा सभी महिलाओं को सब्जियों के बीज वितरित किए गए। प्रशिक्षण को आयोजित करवाने में गौतम लाल, शंकर लाल, लाल शंकर, रमीला आदि का सहयोग रहा। कार्यशाला में नई बस्ती गांव की 50 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।

सरकार लेती कर्ज, कौन निभावे फर्ज

राज्य सरकार हर साल खर्चे पूरा करने के लिए उधार ले रही है, वहीं बजट प्रावधान के हजारों रुपए खर्च ही नहीं हो पा रहे हैं। इससे उधार ली गई राशि का सदुपयोग ही नहीं हो रहा वहीं दूसरी ओर सरकार पर ब्याज का भार बढ़ रहा है। पांच साल पहले करीब 20 हजार करोड़ रुपए तो बीते वित्तीय वर्ष में करीब 25 हजार करोड़ रुपए बिना खर्च हुए रह गए। सरकार चाहे किसी भी दल की हो लेकिन इस बीमारी का तोड़ नहीं निकल रहा।

बजट राशि खर्च नहीं होने को लेकर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में भी लगातार सवाल उठता रहा है। अर्थशास्त्री भी अक्सर राज्य पर कर्जभार बढ़ने को लेकर चिंता जताते रहते हैं। सीएजी ने खुलासा किया है कि प्रदेश में 178 योजनाओं पर एक धेला भी खर्च नहीं हुआ वहीं वर्ष 2020-21 में 3 हजार 278 करोड़ रुपए से अधिक की 178 योजनाओं का खाता ही नहीं खुला। *(रा.प., 24.10.22)*

राज्य वृक्ष पर चल रही कुल्हाड़ी

प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कंपनियां राज्य वृक्ष खेजड़ी की बेतहाशा कटाई करा रही है। खबर है कि जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों के नजदीकी क्षेत्रों में 2000 से भी ज्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। इससे प्रदेश की बेशकीमती संपदा और पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

राजस्थान वृक्षों की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति देने वाला प्रदेश है। लेकिन सरकारी विभागों की अनदेखी के चलते गुपचुप में यह सब हो रहा है। कंपनियां रात को डीजल, एसिड से खेजड़ी पर स्प्रे करवाती हैं ताकि पेड़ सूख जाए, बाद में एसीबी से उन्हें उखाड़ा जा रहा है। बताया गया है कि खेजड़ी के पेड़ों की गिनती कर वन विभाग को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, बावजूद इसके रेगिस्तानी वन संपदा पर कुल्हाड़ी चल रही है। *(दै.भा., 13.11.22)*

दिखावा साबित हो रही राजश्री योजना

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना दिखावा साबित हो रही है। योजना में बेटियों को पहली किस्त के 2500 रुपए तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी किस्त के 2500 रुपए को लेकर अभिभावकों को जानकारी ही नहीं होती। इस कारण प्रदेश की 7.69 लाख बेटियों को दूसरी किस्त नहीं मिली। इससे 1540 करोड़ रुपए अटकने की नौबत आ गई है।

इस योजना में बच्चियों को उनके जन्म से 12 वीं पास करने तक सरकार 6 किस्तों में50 हजार रुपए देती है। दूसरी किस्त के भुगतान का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग का होता है, जबकि बजट महिला बाल विकास विभाग देता है। लाभार्थी बच्चियों के माता-पिता को पता ही नहीं होता कि दूसरी किस्त कैसे मिलेगी। दूसरी किस्त नहीं मिलने पर आगे की किस्तें नही मिलेगी। ऐसे में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक बच्ची को 47500 रुपए का नुकसान हो रहा है। *(दै.भा., 19.12.22)*

नहीं पहुंचा मिड-डे-मील का पैसा

प्रदेश की 11 पंचायती राज संस्थाओं की ओर से मिड-डे-मील की 3 करोड़ रुपए की राशि स्कूलों के लिए ट्रांसफर नहीं हुई। केंद्र प्रवर्तित योजना मिड-डे-मील की इस राशि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ट्रांसफर किया जाना था। गौरतलब यह है कि चार साल पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद अभी तक पैसा नहीं दिए जाने से स्कूलों में न केवल पोषाहार का काम, बल्कि नामांकन, उपस्थिति और ठहराव के काम अटक गए।

यह जानकारी सीएजी रिपोर्ट में सामने आई है। जिन पंचायती राज संस्थाओं ने पैसा रोका, उनको अब नोटिस दिया गया तो उन्होंने ऐसे तर्क गिनाए, जिनका कोई आधार सामने नहीं आया। असल में मिड-डे-मील योजना केंद्र प्रवर्तित वह योजना है, जिसे बच्चों के स्कूलों में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति को बढ़ाने तथा बच्चों के पोषण के स्तर पर सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। सीएजी ने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने का भी अंदेशा जताया है। *(दै.भा., 27.10.22)*

सम्मान निधि में अपात्रों की हुई पहचान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन, सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों के डेटा को 'क्लीन' करने के लिए आधार लिंक वाला चौथा डिजिटल फिल्टर आजमाया तो लाभार्थी किसानों की संख्या 6 महीने में 1.86 करोड़ कम हो गई।

11वीं किस्त में इस योजना का लाभ 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला, जो 12वीं किस्त में घटकर 8.58 करोड़ रह गया। कृषि मंत्रालय ने किसानों के डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए तीन फिल्टर पहले से लगाए थे। लेकिन आधार लिंक्ड पेमेंट के रूप में चौथा फिल्टर लगाया तो लाभार्थियों की संख्या घटते गई। यह फिल्टर फर्जी लाभार्थियों को पहचानने के लिए हैं। इनमें जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा है। डेटा को यूआईडीएआई सर्वर पर भेजकर पहचान होती है। लाभार्थी के बैंक खाते का प्रमाणीकरण होता है। *(दै.भा., 07.12.22)*

प्रदेश में बढ़े अपराध..लोगों ने कहा कहीं भी नहीं सुरक्षित

राजस्थान में अपराध बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक है। सरेआम मारपीट से लेकर गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों की खरीद-फरोख्त जैसी घटनाओं ने शर्मसार किया है। राजस्थान पत्रिका द्वारा हाल ही किए गए सर्वे में 69.2 फीसदी लोगों ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है।

सर्वे में करीब 79.9 फीसदी लोगों ने माना कि अपराध बढ़ने का बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता है। सर्वे में 81.5 फीसदी लोगों के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में 51 हजार और वर्ष 2021 की तुलना में इस वर्ष 28 हजार से अधिक अपराधिक प्रकरण बढ़े हैं। यह हालात तो तब है, जब थानों में छोटे-मोटे अपराध तो दर्ज ही नहीं होते। *(रा.प., 26.11.22)*

अपात्रों ने उठा ली वृद्धावस्था पेंशन

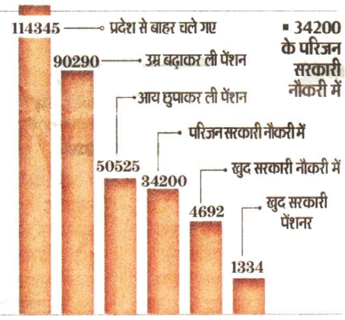

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पिछले तीन साल में कई लोगों ने ई-मित्र के जरिए उम्र बढ़ाकर, आय छुपाकर और परिजन के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन ले ली। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा दौसा और करौली जिले में हुआ है। यहां करीब 25 हजार लोग जनाधार कार्ड में उम्र को बदलवा कर बुजुर्ग बन गए और पेंशन लेना शुरू कर दिया।

इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पड़ताल में सामने आई है। विभाग अब उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। दौसा में 14200 और करौली में 10904 मामले सामने आ चुके हैं। अन्य कई जिलों में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में करीब 94 लाख लोग हर माह वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं जिस पर करीब 8800 करोड़ रुपए केंद्र व राज्य सरकार खर्च कर रही है। *(दै.भा., 30.12.22)*

जनता के अधिकार को बना रहे कमजोर

प्रदेश में सरपंच, प्रधान व सभापति प्रथम अपील पर ठीक से सुनवाई नहीं करके सूचना का अधिकार कानून को कमजोर बना रहे हैं। ग्रामीण और शहरी संस्थाओं के ये मुखिया सीधे तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और इनके सही तरीके से सुनवाई नहीं करने के कारण राज्य सूचना आयोग में अपीलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य के नियमों में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों की प्रथम अपील सुनने का अधिकार सरपंच, प्रधान व सभापति को दिया गया है। राज्य सूचना आयोग पहुंच रही अपीलों को देखें तो सामने आ रहा है कि पंचायती राज संस्था व शहरी निकाय दोनों ही जगह निर्वाचित संस्था प्रमुख प्रथम अपीलों पर ठीक से सुनवाई नहीं कर रहे, जो कि कानून की भावना के खिलाफ है। *(रा.प., 12.10.22)*

सामने आया करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा

मकान और जमीनों की रजिस्ट्री में सालभर पहले सात करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। इस पर बड़ी कार्रवाई करना तो दूर सरकार ने अब तक किसी की जिम्मेदारी तक तय नहीं की। उलटे, मंत्री और अफसरों के बदलते ही पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मामला भी दफन करने में जुट गया।

विभाग की करतूत यही नहीं रुकी, बल्कि घोटाले की राशि जनता से ही वसूलने का काम होता रहा। जिन प्रभावित लोगों ने रजिस्ट्री की मूल रकम जमा करवा दी, उन्हें ब्याज व पेनल्टी के नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं, मूल रकम जमा नहीं होने पर कुर्की तक के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबकि, प्रभावित रजिस्ट्री की राशि पहले ही दे चुके हैं। खास यह है कि विभाग ने जांच के लिए हाईपावर कमेटी गठित की, लेकिन मंत्री और अधिकारियों के बदलते ही सब कुछ दबा दिया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले अभी पकड़ से बाहर हैं। *(रा.प., 30.11.22)*

देश में बढ़ रही है आर्थिक असमानता

नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत अभी विश्व स्तर पर आर्थिक दौड़ में बहुत पीछे है। इसका मूल कारण देश में आर्थिक असमानता होना है। यहां ज्यादातर धनराशि अमीरों की जेब में है, तो गरीब और गरीब होता जा रहा है।

देश में जो आर्थिक असमानता है, उसे दूर करने के लिए सबको मिलकर कुछ करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहां टैक्स सिस्टम को सही करने की जरूरत है। यदि इसकी शुरुआत होती तो असमानता पर चोट होती। देखा जाए तो अभी भी ग्रामीण अंचलों में आर्थिक रूप से कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।

(रा.प., 03.11.22)

पूरी नहीं हुई बजट की कई घोषणाएं

राज्य की अशोक गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष की ओर बढ़ रही है, लेकिन पहले साल की एक चौथाई बजट घोषणाएं अब तक अधूरी है। दूसरे साल की करीब 35 व तीसरे वर्ष की 57 प्रतिशत घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की मानें तो वर्ष 2016-17 तक की कुछ घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं।

मौजूदा वित्तीय वर्ष की करीब 20 प्रतिशत घोषणाओं को लेकर अभी कोई हलचल नहीं हैं और करीब पौने तीन सौ घोषणाएं स्वीकृति की प्रक्रिया पार कर पाई है। जहां तक पिछले साल की बात करें तो 43 प्रतिशत ही पूरी हो पाई है। चार सौ से अधिक घोषणाओं पर काम चल रहा है। घोषणाएं कागजों में अटकी होने से जन सुविधाओं पर असर हो रहा है, वहीं इन पर लागत भी बढ़ रही है। *(रा.प., 17.10.22)*

ट्रस्टों को हजारों करोड़ रुपए की छूट

लोक कल्याण के नाम पर ट्रस्ट और संस्थाओं ने नियम विरुद्ध तरीकों से इनकम टैक्स छूट हासिल की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने ट्रस्ट और संस्थाओं से जुड़े 6.89 लाख मामलों की जांच के बाद यह खुलासा किया है। आयकर विभाग ने इनमें से 3.7 प्रतिशत यानी 25 हजार मामलों की जांच की है।

महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 23 राज्यों में 21 हजार से अधिक ट्रस्ट और संस्थाएं ऐसी थीं, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12एए के तहत रजिस्टर्ड नहीं थीं, इसके बावजूद उन्होंने इसके तहत मिलने वाली छूट हासिल कर ली। यह छूट 18 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक थी। संसद के शीतकालीन सत्र में कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। *(दै.भा., 26.12.22)*

बैटरियों की खरीद-फरोख्त में घोटाला

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के अफसरों ने बाजार कीमत से 25 प्रतिशत ज्यादा दरों पर एम.इंफो सिस्टम लि. कंपनी से बैटरियां खरीदी और पुरानी बैटरियां कंपनी को औने-पौने दामों में बेच कर करीब 5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी।

सहकारी बैंक ने जो बैटरियां 6988 रुपए की दर से खरीदी, उसी कंपनी से आरआइएसएल ने 10752 रुपए की दर में ली। आरआइएसएल द्वारा 10737 बैटरियां प्रदेश के जिला स्तर के सरकारी दफ्तरों के लिए खरीदी गई थी, ताकि बिजली कटौति के दौरान सरकारी विभागों में जनता के काम न अटके। *(दै.भा., 11.11.22)*

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए 25,307 करोड़ रुपए (3.1 बिलियन डॉलर) की योजना का ऐलान किया। यह कार्ययोजना 2023 से लेकर 2027 के बीच लागू होगी।

उन्होंने मिस्र के शर्म अल-शेख में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-27) में राष्ट्राध्यक्षों, वित्तीय संगठनों, टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिभागियों की बैठक में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि युद्ध की तुलना में जलवायु परिवर्तन से तीन गुना अधिक लोग प्रभावित होते हैं। पूर्व सूचना प्रणाली के लिए 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सम्मेलन में दुनियाभर के नेताओं व अधिकारियों समेत 45 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। *(रा.प., 09.11.22)*

विश्व को समृद्धि की राह सिखाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जी-20 के अध्यक्षता काल में गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के युद्ध से मुक्ति व हिंसा के प्रतिरोध के साथ शांति, समाधान एवं समृद्धि की राह दिखाएगा। मोदी ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी-20 के नए प्रतीक चिन्ह व नारे का लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा कि 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का नारा भारत के संस्कारों व संस्कृति से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए प्रतीक चिन्ह में कमल के पुष्प पर विराजित पृथ्वी व कमल की 7 पंखुड़ियों के माध्यम से सातों महाद्वीपों की एकजुटता और सौहार्द से समृद्धि एवं प्रगति का संदेश मिलता है। भारत एक दिसम्बर 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा। मोदी ने कहा, भारत विकासशील देशों के दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी प्रथम विश्व या तृतीय न हो, बल्कि केवल एक विश्व हो। *(रा.प., 09.11.22)*

हो जाएगा जैव विविधता का सफाया

जलवायु और भूमि उपयोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 2100 तक दुनिया की एक-चौथाई से भी अधिक जैव विविधता का सफाया हो जाएगा। यह शोध दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और यूरोपीय आयोग की टीम की ओर से किया गया है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने नए उपकरण का उपयोग कर पाया कि आपस में जुड़ी प्रजातियों के नुकसान को टाला नहीं जा सकता।

रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक धरती 6-10 फीसदी तक जानवरों और वनस्पतियों को खो देगी। सदी के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 27 फीसदी हो जाएगा। विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि अब तक पृथ्वी की जैव विविधता पर ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को कम करके आंका गया है। सुधार नहीं किया तो हम धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण चीजों को खो देंगे। *(रा.प., 18.12.22)*

महिला के जीवन स्तर में कोटा प्रथम

महिला और बाल सुरक्षा, अपराध, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में राजस्थान के जिलों की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। साल 2030 तक गरीबी मिटाने और समृद्धि लाने के टार्गेट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से यह स्टडी कराई गई। सभी 33 जिलों में सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल (सतत् विकास लक्ष्य) के 55 मानकों व 13 लक्ष्यों पर कराए गए सर्वे में सामने आया कि पहली बार सात जिले रेड केटेगरी में हैं। यानी इन्होंने 100 में से 50 से भी कम अंक हासिल किए हैं।

कोटा की स्थिति प्रदेश में सबसे बेहतर है। कुल 59.30 अकों के साथ कोटा नंबर एक पर है। लेकिन यह भी यलो केटेगरी में शामिल है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 100 में से 65 या अधिक स्कोर पाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रथम पायदानों तक पहुंचा हो। *(दै.भा., 14.10.22)*

जलवायु संरक्षण में भारत सबसे आगे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जलवायु संरक्षण और प्रकृति की आराधना भारतीय संस्कृति और परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं। आज भारत जलवायु संरक्षण में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। अब दुनिया समझ गई है कि पर्यावरण संतुलन के लिए संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रयासों के कारण ही यह संभव हुआ है।

बिरला ने यह बातें संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित परिबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन पर कही। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें वनों की सुरक्षा के साथ ही देश में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। कानूनों को लागू करते समय अधिकारियों को उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिनका जीवन और आजीविका वनों पर निर्भर है। *(रा.प., 20.12.22)*

जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न पर प्रभाव

यूनिसेफ की आकलन रिपोर्ट 2021 में चौंकाने वाली चेतावनी सामने आई है। यूनिसेफ के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों में सार्क देशों के भविष्य को सबसे चुनौतीपूर्ण केटेगरी में पाया गया है। यूनिसेफ की इस चेतावनी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टीम ने 21 साल में जलवायु परिवर्तन के डेटा पर रिसर्च किया तो सामने आया कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, यूपी और इससे सटे देश नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान में आने वाले सालों में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा।

इन देशों और भारत के राज्यों में रिवर बेसिन स्किल यानी नदियों की आवक क्षमता बेहद कम हो गई है। बहाव क्षेत्र में कब्जा होने से बारिश का पानी नदियों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में सार्क देशों के लिए खाद्यान्न का कटोरा कहलाने वाले इन क्षेत्रों में धान गेहूं की पैदावार सिमट कर 25 फीसदी भी नहीं बचेगी। *(दै.भा., 19.12.22)*

आजादी के 100वें साल 'विजन-2047 पर शुरू हुआ काम

कान्फ्रेंसः केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना

नियमों का सरलीकरण, शहरी व डिजिटल आधारभूत ढांचा, एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, कौशल विकास, औधोगिक विकास, उत्पादन, महंगाई पर नियंत्रण, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा निवेश, आवासन, रोजगार सृजन, फसल विभेदीकरण, ग्रामीण उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री।

केंद्र सरकार ने आजादी के 100वें साल के लिए विकास के मॉडल 'विजन-2047 पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 12 सूत्री राष्ट्रीय एजेंडा राज्यों की भागीदारी से तैयार होगा, जिस पर 5 से 7 जनवरी तक होने वाली मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में विस्तृत चर्चा होगी।

राज्य में इसकी तैयारी के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पहली बैठक ली। नीति आयोग की ओर से आयोजित होने वाली मुख्य सचिव कान्फ्रेंस की थीम 'विकसित भारत- अंतिम पड़ाव तक पहुंच' रखी गई है। इससे केंद्र - राज्य संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। *(रा.प., 05.11.22)*

स्टार्टअपः मिल सकेगा गारंटी मुक्त ऋण

केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत स्टार्टअप की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार स्टार्टअप को तय अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराएगी।

इस स्कीम के तहत सिर्फ उन स्टार्टअप को ऋण दिया जाएगा, जो कम से कम एक साल से स्थिर आय दे रहे हैं। यानी बिना गारंटी का ऋण सिर्फ उन स्टार्टअप को दिया जाएगा, जो ऋण वापस करने की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए ट्रस्ट बनाएगी। *(रा.प., 08.10.22)*

राजनीतिक दल चुनावी वादे न करें

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे खोखले चुनावी वादे न करें। जो वादा किया जाए, उसमें ध्यान रखा जाए कि वह आर्थिक रूप से पूरे करने लायक है या नहीं। चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी मतदाताओं को दी जाए। आयोग ने इस मामले में सभी राजनीतिक दलों से राय भी मांगी है।

विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करते हैं। मुफ्त की इस रेवड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। सभी दलों को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि वह चुनावी वादों पर जानकारी नहीं देने और इससे वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाने अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता। *(रा.प., 05.10.22)*

बायो गैस प्लांट से बन रही जैविक खाद

कोटा में पशुपालकों के लिए बनाई गई विशेष देव नारायण योजना के तहत बने देश के सबसे बड़े बायो गैस प्लांट में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। यह खाद डीएपी का जैविक विकल्प बनेगी। इसके अलावा जैविक तरल खाद से सरकारी उद्यान एवं सार्वजनिक हरियाली वाले क्षेत्रों को पोषण मिल सकेगा। यह प्लांट जैविक खाद फॉस्फेट रिच बनाएगा।

इसके अलावा 17 आवश्यक तत्वों वाला जैविक तरल खाद भी बनाएगा। योजना के तहत 1200 पशुपालक परिवारों के 5 हजार सदस्य होंगे। उनसे एक रुपए किलो के भाव से गोबर खरीदा जा रहा है। जिससे रोजाना 21 टन फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एक लाख लीटर जैविक तरल खाद, तीन हजार लीटर कम्प्रेस्ड बायो गैस बनाने की क्षमता है। *(रा.प., 14.12.22)*

स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश अव्वल

राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में अव्वल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक यहां 88 फीसदी लोग स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। हर 10 में से लगभग 9 लोग किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेते हैं।

ग्रामीण इलाकों की 42 फीसदी आबादी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 42 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा सुविधा से वंचित है। ऐसे में बीमा कंपनियों का 2030 तक पूरी आबादी को आरोग्य बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य है। *(रा.प., 23.10.22)*

भारत संभालेगा अब जी-20 की कमान

जी-20 देशों के 17वें शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जी-20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यह जिम्मा ऐसे समय पर संभाल रहा है, जब दुनिया जियो पॉलिटिकल तनाव, मंदी, खाद्यान्नों, अनाज एवं ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और कोरोना के दुष्प्रभावों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि हम जी-20 के हर सदस्य के प्रयासों से इसे वैश्विक कल्याण के लिए लाभकारी बनाएंगे।

भारत एक दिसंबर 2022 से अध्यक्षता संभाल रहा है। जिसकी थीम है 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।' शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होगा। 500 प्रतिनिधियों का पहला दौरा 13-14 फरवरी 2023 को अजंता-एलोरा का होगा। *(दै.भा., 17.11.22)*

स्टार्टअप्स की रेस में आगे बढ़ रहे युवा

प्रदेश में युवा वर्ग सफल स्टार्टअप्स की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान स्टार्टअप्स में देश के चौथे पायदान पर पहुंच गया है। युवा अच्छी कंपनी में मोटे पैकेज छोड़कर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। युवाओं के नवाचार की सोच बड़े व्यवसायों की शक्ल ले रही हैं।

राजस्थान में दो स्टार्टअप्स यूनिकार्न बन चुके हैं। सरकार के साथ-साथ निजी और ग्लोबल निवेशक भी प्रदेश के युवाओं के स्टार्टअप्स में रुचि दिखा रहे हैं। अब तक 2979 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 440 स्टार्ट अप्स से जुड़े लोगों को 24.81 करोड़ रुपए की फंडिंग और 185 को ऋण के रूप में 16.14 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। स्टार्टअप अब केवल आइटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा, चिकित्सा व कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से आगे आ रहे हैं। निवेशक चयनित स्टार्टअप्स में निवेश कर राजस्थान में रहकर यहीं के विकास पर काम करेंगे। *(रा.प., 16.12.22)*

काली कमाई के मामले नहीं जाएंगे ठंडे बस्ते में

आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से काली कमाई के मामले अब ठंडे बस्ते में डालना अब आसान नहीं होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की स्वीकृति के लिए भेजे गए मामलों पर प्रशासनिक विभाग को 3 माह में निर्णय करना होगा। मुख्य सतर्कता कार्यालय पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा।

गृह विभाग की ओर से पांच माह पहले भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ, जांच एवं अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनकी पालना में ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। चार साल पहले बनाए गए भ्रष्टाचार निवारण संबंधी केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों की पालना के लिए देशभर में ऐसी पहल करने में राजस्थान अग्रणी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की स्वीकृति जारी होने में देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा है कि वे खुद भी देरी के कारणों की जानकारी लेंगे। *(रा.प., 20.10.22)*

पद भरे तो मिले भ्रष्टाचार के खिलाफ धार

गृह विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सैनिकों की कमी बनी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 31 पदों की कमी है, वहीं 37 पुलिस निरीक्षकों के पद भी खाली पड़े हैं। सबको मिलाकर ब्यूरो 261 पदों की कमी की मार झेल रहा है जिसके कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ तलवार को धार नहीं मिल पा रही है।

इतने पदों की भारी कमी होने के बावजूद एसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का जज्बा कम नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिंतबर 2022 तक एसीबी अपने पिछले रेकॉर्ड तोड़ते हुए 392 प्रकरण दर्ज किए। जिनमें 360 ट्रैप, 17 आय से अधिक संपत्ति और 15 पद के दुरुपयोग के प्रकरण शामिल हैं। *(रा.प., 05.11.22)*

'मछली' तो आपको ही पकड़वानी है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बी.एल. सोनी ने कहा है कि वे मानते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार है। लोगों को अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन एसीबी इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। एसीबी को एक बार आजमा के देखिए, बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करके देखिए।

कई बार लोग हमसे कहते हैं कि बड़ी मछली... तब हम कहते हैं कि कांटा लेकर खड़े हैं, बड़ी मछलियां आपको ही पकड़वानी है। आपको आगे आना होगा। महानिदेशक बी.एल. सोनी ने यह बात जिला परिषद् कोटा के सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोग रिश्वत नहीं देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। वर्तमान में लोगों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए जागरूकता बढ़ी है। *(रा.प., 04.12.22)*

भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रतिज्ञा पत्र

भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए नागरिकों में जागरूकता के मकसद से केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने छह बिंदुओं का सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। इसे आयोग के विशेष अभियान के तहत पेश किया गया। इसमें मुख्य तौर पर चार क्षेत्रों प्रॉपट्री मेनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और तकनीकी पहल को लिया गया है।

सीवीसी ने सरकारी मंत्रालयों, संस्थानों, विभागों और आम लोगों समेत शेयरधारकों को प्रतिज्ञा लेने के लिए आमंत्रित किया है।

प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया है 'मेरा विश्वास है कि देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह है प्रतिज्ञा पत्र :

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा।
- न रिश्वत दूंगा, न ही लूंगा।
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता से करूंगा।
- जनहित में कार्य करूंगा।
- अपने आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा।
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा।

(रा.प., 02.11.22)

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला

लोक सेवकों के रिश्वत लेने के मामले में प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सजा हो सकती है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं होने पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है।

पांच जजों की संविधान पीठ ने एक मामले पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया है। पीठ में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर.गवई, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, जस्टिस बी.वी. नागरत्न व जस्टिस ए.एस.बोपन्ना शामिल है।

संविधान पीठ ने कहा है कि शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (2), धारा 7 और धारा 13 (1)(डी)के तहत लोक सेवक के अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति है। *(रा.प., 16.12.22)*

संविधान पीठ की 3 अहम टिप्पणियां

1. *संविधान पीठ ने कहा कि अदालतों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए।*
2. *भ्रष्ट अधिकारियों पर मामला दर्ज करना चाहिए और उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए।*
3. *शासन में भ्रष्टाचार के मामलों से ईमानदार अधिकारियों की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है।*

प्रदेश में बीकानेर बनेगा सोलर हब

प्रदेश में बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में तीन हजार मेगावाट का सोलर पार्क विकसित हो रहा है। यह करीब 9 हजार एकड़ में फैला होगा। इसी के साथ अब दो हजार मेगावाट का सोलर पार्क पूगल में विकसित होगा। इससे पहले भी बीकानेर के नजदीक जामसर में पहले से सोलर पार्क विकसित हो चुके हैं।

गौरतलब है कि करीब दो साल से कोयले की कमी से प्रदेश बिजली संकट से जूझ भी रहा है। ऐसे में सरकार ने कोल इंडिया के साथ 1190 मेगावाट बिजली उत्पादन प्लांट लगाने का भी एमओयू किया है। कुल मिलाकर बीकानेर में 13500 मेगावाट से ज्यादा का बिजली उत्पादन होने लगेगा, जो प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन 23 हजार 436 मेगावाट का 50 फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगा। इससे सोलर हब के रूप में बीकानेर के विकसित होने का दावा मजबूत हो जाएगा। *(रा.प., 15.10.22)*

रेगिस्तानी हवा दे रही ऊर्जा को पंख

राज्य के जैसलमेर जिले में चलने वाली तेज हवा पवन ऊर्जा के पंखों के लिए आदर्श मानी जाती है। यहां पवन ऊर्जा से चलने वाली चक्कियां 12 महीने में इतना विद्युत उत्पादन कर रही है कि हमेशा से बिजली की समस्या से जूझने वाला यह सरहदी जिला आज विद्युत हब बन गया है।

आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ देश के प्रमुख उद्योगपति जिले में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाने के लिए आगे आ रहे हैं। यहां पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 8342 हैक्टेयर भूमि का आवंटन विभिन्न कंपनियों को किया गया है। कंपनियां यहां करीब 835.90 मेगावाट की विंड परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रही हैं।

(रा.प., 07.11.22)

बनाएंगे बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन

राज्य में सौर ऊर्जा की भरमार है। इससे अब ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेगी। प्रदेश में 269 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन को देखते हुए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा (सौर व पवन ऊर्जा)उपयोग में ली जाएगी। इससे कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण भी कम होगा। प्रदेश के

बिजली उपभोक्ताओं पर भार

फ्यूल सरचार्ज के नाम पर मौजूदा सरकार में अब तक उपभोक्ताओं पर 11 बार अतिरिक्त भार डाला जा चुका है। पिछली भाजपा सरकार में भी इस सरचार्ज की आड़ में उपभोक्ताओं से यह वसूली की गई थी । उधर, सरकार यह तर्क देकर बचने की कोशिश कर रही है

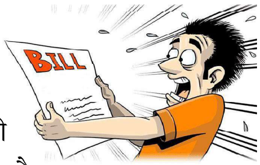

कि उन्होंने टैरिफ दर नहीं बढ़ाई है, जिसका वादा घोषणा पत्र में किया गया था।

राज्य में 1.42 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं। इनमें कृषि उपभोक्ता 14 लाख, बीपीएल श्रेणी के 16 लाख और छोटे घरेलू कनेक्शनधारी (पचास यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता) 41 लाख हैं। इन उपभोक्ताओं के फ्यूल सरचार्ज की राशि सरकार वहन कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका भार भी बाकी उपभोक्ताओं पर ही डाला जा रहा है। *(रा.प., 01.11.22)*

बड़े उद्योगों में यह हाइड्रोजन उपयोग में आएगी। इसके लिए प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विकसित होंगे।

बिजली जब पानी में होकर गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज्यादातर इण्डस्ट्रीज में होता है।अक्षय ऊर्जा से ली गई हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां यह पॉलिसी लागू हो रही है। अभी तक केंद्र सरकार ने यह पॉलिसी लागू की है। *(रा.प., 15.11.22)*

किसान बचा रहे लाखों की बिजली

प्रदेश के गांवों में फसलों के साथ खेतों में सोलर पैनल खड़े नजर आ रहे हैं। किसान इससे न केवल लाखों रुपए की बिजली बचा रहे हैं बल्कि दिन में सिंचाई कर रात की ठंड और जंगली जानवरों के जोखिम से भी बच रहे हैं। पिछले दस सालों में जितने किसानों ने यह तकनीक अपनाई है, उतने आवेदन अब एक साल में कृषि विभाग के पास आने लगे हैं।

अकेले झुंझुनूं जिले की बात करें तो लगभग 5 हजार किसान ऐसे हैं जो खेतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा कर खेती कर रहे हैं और इतने ही आवेदन विभाग के पास लम्बित पड़े हैं। कई किसान सरकार से अनुदान लेकर तो कई सोलर कंपनियों से संयंत्र खरीदकर अपने खेतों में लगा रखे हैं। इससे वे ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई करते हैं और हजारों रुपए का बिजली का बिल भरने से बच रहे हैं। *(रा.प., 13.12.22)*

प्रदेश में सोलर प्लांट का बढ़ेगा दायरा

बंजर व बेकार पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों की राह और आसान हो गई है। किसानों को जमीन के बदले हर साल प्रति हेक्टेयर 80 हजार से 1.60 लाख रुपए लीज राशि (यदि किसान की जमीन पर डवलपर प्लांट लगाता है तो) मिलेगी । इसकी गणना डीएलसी दर के आधार पर होगी। कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के सी कम्पोनेंट में एकरूपता के लिए डिस्कॉम प्रशासन ने लीज राशि तय की है।

इस योजना के लिए फिलहाल प्रदेश में 781 ग्रिड सब-स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं,जहां पानी की कमी के चलते जमीन बंजर हो गई है। इस जमीन से किसानों को कोई आय नहीं हो रही। यदि किसान प्रोजेक्ट लगाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वह डवलपर से एग्रीमेंट कर सकेगा।

(रा.प., 18.10.22)

कार्बन उत्सर्जन से अछूता नहीं है प्रदेश

कार्बन उत्सर्जन (कार्बन फुटप्रिंट) से राजस्थान भी अछूता नहीं है। यहां हर वर्ष 110 से 115 मिलीयन मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। इसमें 34 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा थर्मल पावर प्लांट से और 31 प्रतिशत हिस्सा परिवहन सेक्टर का है। अब हर दिन 70 से 75 हजार टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें ऊर्जा, परिवहन के अलावा औद्योगिक क्षेत्र, कॉमर्शियल वेस्ट, सीवरेज, कचरा व अन्य कारण भी शामिल है। ऊर्जा संरक्षण पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी काम कर रहा है।

अरण्य भवन इण्डो-स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशियेंसी प्रोजेक्ट में शामिल है। यहां 44 प्रतिशत ऊर्जा बचत हो रही है। इसी आधार पर प्रदेश में बिल्डरों द्वारा ग्रीन बिल्डिंग कांसेप्ट से जुडे 19 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। *(रा.प., 14.12.22)*

लोहे की जगह बिछेंगे प्लास्टिक के पाइप

राजस्थान में अब जल जीवन व अन्य पेयजल परियोजनाओं में लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप बिछेंगे। लोहे की जगह 100 से 200 एमएम के पीवीसीओ-ओ (प्लास्टिक) पाइप काम में लिए जाएंगे। इसके लिए सात वर्ष पहले बनी पाइप पॉलिसी-2015 में पीवीसीओ-ओ (प्लास्टिक) पाइप काम में लेने का प्रावधान जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

इंजीनियरों का कहना कि ये पाइप लोहे के पाइप से 25 प्रतिशत तक सस्ते हैं और मजबूती में लोहे के पाइप के बराबर हैं। यह पाइप पहाड़ी इलाकों की जगह सिर्फ मिट्टी वाले इलाकों की पेयजल परियोजनाओं में ही काम में लिए जाएंगे। बड़ी पेयजल परियोजनाओं के खर्च की बात करें तो जितना खर्च अन्य निर्माण सामग्री पर होता है उतना ही अकेले लोहे के पाइप खरीद पर होता है। अन्य सामग्री के मुकाबले लोहे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में खर्च के बोझ से जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का ढांचा चरमराने लगा है। *(रा.प., 31.10.22)*

अच्छी बारिश के बावजूद पानी पैंदे में

प्रदेश में इस साल अच्छी बारिश होने के बाद भी भूजल स्तर एक से दो मीटर तक गिरा है। इसका खास कारण भूजल रिचार्ज के मुकाबले जमीन से पानी का दोहन 151.07 प्रतिशत ज्यादा होना है। जोधपुर के भूजल स्तर में तो 4 मीटर तक की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान सहित सभी राज्यों के भूजल स्तर पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड निगरानी क रता है।

प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक भूजल का बहुत ज्यादा दोहन होने के कारण अतिदोहित (डार्क जोन) में आ गए हैं। चिंताजनक यह है कि प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित स्थिति में बचे हैं। प्रदेश में इस साल भूजल 12.13 बीसीएम (अरब घन मीटर) रिचार्ज हुआ है। जबकि 16.56 बीसीएम पानी खेती, पेयजल व औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन से निकाला गया। *(दै.भा., 13.11.22)*

पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी

पीएचईडी ने जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 करोड़ से ज्यादा लागत की लक्ष्मण डूंगरी, उद्योग नगर और भट्टाबस्ती पेयजल परियोजनाओं के संबधित फर्मों को कार्यादेश जारी कर दिए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि फर्मों ने इन पेयजल परियोजनाओं का काम टेंडर की निर्धारित दर से 11 फीसदी तक कम दरों पर हाथ में लिया है।

इस पर पीएचईडी के ही इंजीनियरों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि कम दरों पर टेंडर लेकर फर्में निम्न गुणवत्ता वाले पाइप व अन्य निर्माण सामग्री काम में लेती है। यहीं से ठेका फर्म और इंजीनियरों के गठजोड़ से पेयजल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है और परियोजनाएं आमजन के लिए नासूर बन जाती है। *(रा.प., 15.10.22)*

जल क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक निवेश

जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन पर पड़ रहे बुरे असर को कम करने में भारत वैश्विक रूप से अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। इस मकसद के साथ 7वें इंडिया वॉटर वीक की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ग्रेटर नोएडा में की गई। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल संकट की प्रासंगिकता को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2024 तक देश में जल के क्षेत्र में 210 मिलियन डॉलर का निवेश निश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में जल के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बन गया है। जल पर काम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5पी यानी पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेडिंग, पार्टनरशिप, पीपल्स पार्टिसिपेशन्स और परसुएशन का मंत्र दिया है। इस पर भारत में काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए सरकार ने अटल भूजल योजना शुरू की है। इसमें सात राज्यों के 81 जिलों में काम शुरू कर दिया गया है।

(रा.प., 02.11.22)

जल जीवन मिशन के टेंडर में गड़बड़झाला

जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में 10 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काम होने हैं। इसके लिए जलदाय विभाग की ओर से जारी टेंडर में बड़ा गड़बड़झाला चल रहा है। चहेती फर्मों को काम दिलाने, मनचाहे तरीके से शर्तें जोड़ने और हटा देने से निर्धारित दर से 42 प्रतिशत तक ज्यादा की दरें आई है। इससे सरकार को 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।

गौरतलब यह है कि एक्ट के विपरीत होने और गड़बड़ी के बावजूद टेंडर निरस्त नहीं किए गए। जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट लागत में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत की भागीदारी है। प्रोजेक्ट के टेंडर में हो रहे गड़बड़झाले की गूंज लोकसभा में भी उठ चुकी है और पाली के सांसद पी.पी.चौधरी ने मामला उठाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। *(रा.प., 14.12.22 से 16.12.22)*

निकाल लिया जाता है जमीन में जाने वाला 60 प्रतिशत पानी

देश में एक साल में जमीन के अंदर जाने वाले पानी की कुल मात्रा का 60.08 प्रतिशत पानी निकाल लिया जाता है। देश के लिए वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है और सालाना 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाल लिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय भूजल बोर्ड की सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में यह खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों (14 प्रतिशत) को 'अतिदोहन' की श्रेणी में रखा गया है। इन इकाइयों में भूजल दोहन की मात्रा वार्षिक भूजल रिचार्ज से ज्यादा है। देश में 2004 में जमीन के अंदर जाने वाले पानी की कुल मात्रा का 58 फीसदी निकाला गया जो 2009 में बढ़कर 61 और 2011 में 62 फीसदी दर्ज किया गया। वर्ष 2013 में यह 62, 2017 में 63, 2020 में 62 और 2022 में करीब 60 फीसदी रहा। भूजल रिचार्ज का मुख्य स्रोत मानसूनी बारिश है। *(रा.प., 11.11.22)*

पूरा बजट कभी काम ही नहीं आता

देश की कुल आबादी में 67.7 फीसदी हिस्सा रखने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए केंद्र सरकार योजनाओं में रकम तो दिल खोल कर जारी करती है, लेकिन समय पर खर्च नहीं हो पाता। योजनाओं के आकलन से पता चलता है कि महिला व बाल विकास के लिए केंद्र सरकार ने छह साल में प्रतिवर्ष बजट बढ़ाया, लेकिन किसी भी साल में पूरा खर्च नहीं हुआ।

शिक्षा, महिला, बाल, युवा व खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत 346वें प्रतिवेदन में इस पर चिंता जताई है और कहा है कि बजट का शत-प्रतिशत इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के साथ-साथ किसी भी स्तर पर चूक के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। *(रा.प., 21.12.22)*

प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ नसबंदी हो रही फेल

राजस्थान में पिछले 6 साल के दौरान 8475 नसबंदी केस फेल हो चुके हैं। राजस्थान से ज्यादा नसबंदी फेल किसी भी राज्य में नहीं होती। सैंकड़ों मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को इस अवधि में 25.5 करोड़ रुपए हर्जाना या मुआवजा भुगतना पड़ा है। हर साल औसतन 1400 से 2500 नसबंदी फेल होने की बात सामने आई है।

पिछले छह सालों में प्रदेश में नसबंदी के 8475 केस फेल होने पर पीड़ितों को 25 करोड़ 39 लाख 90 हजार रुपए मुआवजा देना पड़ा। इस अवधि में नसबंदी के बाद 45 महिलाओं की मौत हो गई। उनके परिजनों को 69 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया। गौरतलब यह है कि नसबंदी की शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं। पुरुष अब भी केवल एक प्रतिशत ही नसबंदी कराते हैं। *(दै.भा., 04.11.22)*

महिलाओं में बढ़ी बचत करने की ललक

देश में 26 से 30 साल तक की आयु वर्ग वाली महिलाओं में भी अब बचत की ललक देखने को मिल रही है। रिटर्न दाखिल करने वाली 46 प्रतिशत युवा महिलाओं ने आयकर कानून की धारा 80सी की कटौती सीमा का पूरा फायदा लिया। टैक्स फाइलिंग में मदद करने वाली फिनटेक कंपनी क्लियर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 प्रतिशत महिलाओं ने इस छूट का इस्तेमाल नहीं किया। एक लाख से 1.5 लाख रुपए तक कटौती का फायदा 10 प्रतिशत महिला करदाताओं ने उठाया। वहीं 50 हजार से एक लाख तक की छूट का लाभ भी इतनी ही करदाताओं ने लिया। 50 हजार रुपए तक छूट का लाभ उठाने वाली महिलाओं का हिस्सा 24 प्रतिशत रहा। इस आयु वर्ग की 34 प्रतिशत महिलाओं ने इस साल रिटर्न दाखिल किया। *(दै.भा., 31.10.22)*

आदिवासी बेटी का हो संपत्ति में अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब गैर-आदिवासी की बेटी पिता की संपत्ति में समान हिस्से की हकदार है तो आदिवासी बेटी को इस तरह के अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे की जांच करने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार, पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के लिए समान हिस्से की गारंटी देने वाला कानून अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता। ऐसे में अनुसूचित जनजाति की बेटियां पिता की संपत्ति की हकदार बनने से वंचित रह जाती है। *(दै.भा., 11.12.22)*

प्रदेश में महिला किसान उपजा रही अन्न

राजस्थान में पुरुषों से ज्यादा महिला किसान अन्न उपजाकर देश दुनिया का पेट भर रही है। ई-श्रम पोर्टल 2022 के अनुसार राज्य में कुल 1.25 करोड़ किसान है। इनमें 51.01 फीसदी महिलाएं और 48.99 फीसदी पुरुष किसान हैं। खास बात यह है कि अब प्रदेश की महिला किसान अंगूठा छाप नहीं बल्कि उच्च शिक्षा लेकर खेती में नवाचार कर रही हैं।

कई महिलाएं खेती में नई तकनीक अपना कर कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले रही हैं। यही नहीं, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हो रही हैं। तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब महिला किसानों से जैविक उत्पाद सीधे खेतों से खरीद कर दिल्ली, मुंबई व गुरुग्राम के बड़े स्टोर व पांच सितारा होटलों में बेच रही हैं। *(रा.प., 18.11.22)*

बेटियों को है साइकिल का इंतजार

सरकार ने नौवीं कक्षा की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की घोषणा कर रखी है। लेकिन राज्य की करीब साढ़े तीन लाख बेटियों को स्कूल खुलने के चार महीने बाद भी साइकिल नहीं मिली है। इससे उन्हें पैदल ही स्कूल जाना पड़ रहा है। खासतौर पर गांवों में पढ़ने वाली बालिकाओं को स्कूल तक लम्बी दूरी पार करना एक बड़ी समस्या बन रही है।

इस बार बेटियों को साइकिल की जगह ई-वाउचर दिया जाना है। इसके जरिए वे नजदीकी वेंडर से साइकिल ले सकेंगी। लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग की लेटलतीफी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। *(रा.प.,12.11.22)*

महिला टीचर्स के लिए बनेंगे टॉयलेट

आजादी के 75वें वर्ष पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर प्रदेश के 68 हजार स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवार रही 1.34 लाख से ज्यादा महिला शिक्षकों को अलग टॉयलेट तक नहीं दे पाए हैं। उन्हें छात्राओं के टॉयलेट में जाना पड़ता है। प्रदेश के 6803 स्कूलों में तो टॉयलेट ही नहीं है। एक प्रधानाचार्य ने तो प्रधानमंत्री तक को महिला टीचर्स की इस परेशानी के लिए पत्र लिखा है।

अब जाकर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहल की है। स्कूलों में अब महिला स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट होंगे। विभाग ने हाल ही सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि स्कूलों का निरीक्षण करें। रिपोर्ट तैयार करें और टॉयलेट नहीं होने पर समग्र शिक्षा अभियान के बजट, भामाशाहों या सीएसआर फंड से इनका निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें। *(दै.भा., 15.12.22)*

केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट संजीवनी

सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत हेलीकॉप्टर को घायल तक पहुंचाने का लक्ष्य 20 मिनट का रखा गया है। इससे घायल को पहले एक घंटे (गोल्डन आवर) में उपचार मिल सकेगा।

हेलीकॉप्टर में एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और एक डॉक्टर की भी व्यवस्था होगी। एक पायलट के पास आवश्यक चिकित्सा उपकरण मौजूद होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हेलीपैड बनाने की इस योजना पर काम शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब दुर्घटना होती है तो कई बार वहां एंबुलेंस को पहुंचने में काफी देर हो जाती है, इससे निपटने के लिए हेलीपैड बनाने की पहल शुरू की गई है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर ऐसे ही हेलीपैड बनाए जाएंगे।

(रा.प., 23.10.22)

ट्रक-लॉरी हादसों में 14,622 मौतें

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ट्रक या लॉरी हादसों में 14,622 मौतें हुई है। सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटनाओं का कारण 60 फीसदी ओवर स्पीड है जिसकी वजह से 56 फीसदी मौतें हुई है।

जयपुर की बात करें तो ट्रैफिक दुर्घटनाओं और उनमें हुई मौतों के मामले में जयपुर, मुम्बई, पुणे, सूरत जैसे बड़े शहरों से भी आगे है। जयपुर पिछले साल टैफिक दुर्घटनाओं के मामले में देश के बड़े 53 शहरों में छठे और इन दुर्घटनाओं में हुई मौतों के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। साल 2021 में जिले में 3205 सड़क दुर्घटनाएं हुई। जिनमें 2745 लोग घायल हुए। इनमें 1106 लोगों की मौत हो गई। पिछले दो वर्षों में जिले में सड़क हादसों में 2186 लोगों की मौत हुई। साल 2020 की तुलना में साल 2021 में मौतें 2.41 फीसदी बढ़ी हैं। *(रा.प., 07.12.22)*

पैदल व साइकिल वालों को दें जगह

मिस्त्र में कॉप-27 समिट को ध्यान में रखकर किए गए सर्वेक्षण में पता चलता है कि 64 प्रतिशत लोग पैदल और साइकिल सवारों को चलने के लिए सड़कों पर ज्यादा जगह देने के पक्ष में हैं। भले ही इसके लिए मोटर वाहन चालकों को समझौता करना पड़े। शहरों में रहने वाले भारतीय जलवायु परिवर्तन को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहें हैं। इसके बुरे प्रभावों से निपटने के लिए वे नीतिगत बदलावों का समर्थन करते हैं।

सर्वे में 58 फीसदी भारतीयों का मानना है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली यात्राओं जैसे फ्लाइट और डीजल वाहनों पर ज्यादा टैक्स वसूला जाना चाहिए। करीब 57 फीसदी लोगों ने सुझाव दिया है कि शहर के मध्य वाले क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इन क्षेत्रों में व्हीकल मुक्त जोन बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। *(दै.भा., 14.11.22)*

राहगीरों के लिए फुटपाथ ही नहीं?

सड़क पर चलने का पहला अधिकार राहगीर का है। इसलिए दुनिया के कई देश राहगीरों की राह सुगम कर उन्हें सम्मान दे रहे हैं। हमारे देश प्रदेश में हालात इससे बिल्कुल उलट है। राजस्थान में तो फुटपाथों को घटाकर या खत्म कर सड़कों को वाहन फ्रेंडली बनाने का काम चल रहा है। शहरों में 74 प्रतिशत से ज्यादा सड़कों पर फुटपाथ नहीं है। जहां है वहां भी अधिकांशतः राहगीरों के चलने लायक नहीं है।

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट में ये हालात सामने आए हैं। पिछले कुछ सालों से यह आंकड़ा बढ़ गया है। वाहन फ्रेंडली बनाने के लिए सड़कें चौड़ी की जा रही है। असर यह है कि पैदल चलने वाले राहगीरों की सड़क पर चलना मजबूरी बन गई है। इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसमें चारों स्मार्ट सिटी जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर के अलावा जोधपुर, अलवर जैसे बड़े शहर शामिल हैं। *(रा.प., 27.10.22)*

तेज गति से हाईवे पर हादसे का खतरा

वाहन की तेज गति के कारण दुर्घटना का सबसे ज्यादा खतरा हाईवे पर होता है और वहीं लोग कार में पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। उधर, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस भी हाईवे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चालान और समझाइश का काम शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा है।

जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में यातायात पुलिस ने अब तक कार के पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने वाले 1800 लोगों के चालान किए हैं। इस कार्रवाई में ज्यादातर चालान शहरी क्षेत्र में किए हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाईवे पर मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म विकसित करना आवश्यक है।

अभी हाईवे पर जो इंटरसेप्टर खड़ी होती है वही कार की स्पीड और सीट बेल्ट की मॉनिटरिंग करती है। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही टोल पर भी जांच की जानी चाहिए। परिवहन विभाग की टीमें केवल ट्रकों को ही नहीं देंखे, बल्कि अन्य वाहनों पर भी ध्यान दें।

(रा.प., 26.12.22)

नाबालिगों का वाहन चलाना है गैर कानूनी

शहर में अभिभावकों की सहमति से नाबालिग वाहन दौड़ा रहे हैं और आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी है। सहमति इसलिए कि किशोर वाहनों का सर्वाधिक उपयोग स्कूल-कोचिंग तक आने-जाने में कर रहे हैं। यह बात उनके माता-पिता को भी पता है और स्कूल प्रशासन को भी पता है। स्कूल छुट्‌टी के बाद बड़ी संख्या में नाबालिग वाहन दौड़ाते सड़कों पर दिखाई देते हैं, मगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनका चालान तो दूर, रोकती-टोकती भी नहीं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिगों का वाहन चलाना गैर कानूनी है और माता-पिता व वाहन स्वामी पर कार्रवाई का प्रावधान है।

यदि किशोर अभिभावक की सहमति से वाहन चलाता है तो अभिभावक या वाहन स्वामी को 25 हजार रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की सजा तक हो सकती है। वाहन का पंजीयन भी एक वर्ष के लिए रद्द किया जा सकता है। कार्रवाई होने पर नाबालिग वाहन चालक का लाइसेंस 25 वर्ष की आयु तक नहीं बन सकता। *(रा.प., 30.11.22)*

उपभोक्ता फैसले

हाउसिंग बोर्ड 2005 की कीमत पर मकान आवंटित करे

जयपुर निवासी अजय फाटक ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि वह हाउसिंग बोर्ड की कल्पतरु योजना 1987 में पंजीकृत आवेदक था। हाउसिंग बोर्ड ने 2005 की उच्च आय वर्ग लॉटरी में उनका नाम होने के बावजूद, उन्हें वर्ष 2006 की सूची से हटा दिया। साथ ही बाद में उनकी वरीयता का उल्लंघन कर उनसे कम वरीयता वालों को मकान आवंटित कर दिए। उन्होंने बताया कि पहली लॉटरी को बिना किसी कारण निरस्त किया गया था। मामले की सुनवाई कर जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया। हाउसिंग बोर्ड मामले को राज्य आयोग में ले गया वहां भी फैसला उनके हक में हुआ।

फैसले के खिलाफ हाउसिंग बोर्ड ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में रिविजन याचिका दर्ज कराई। राष्ट्रीय आयोग ने हाउसिंग बोर्ड की रिविजन याचिका को खारिज कर दिया और राज्य उपभोक्ता आयोग व जिला उपभोक्ता आयोग के उन फैसलों को बरकरार रखा, जिनमें हाउसिंग बोर्ड की मानसरोवर एसएफएस योजना में परिवादी अजय फाटक को वर्ष 2005 की कीमत व क्षेत्रफल के आधार पर मकान आवंटित करने और जुर्माना देने का निर्देश दिया गया था। *(दै.भा., 04.10.22)*

बैंक को भारी पड़ा क्रेडिट कार्ड खाते में पैसा जमा नहीं करना

राजस्थान के चूरू जिले के साहवा गांव निवासी किसान रामस्वरूप माली ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा में 8 दिसंबर, 2017 को 54 हजार रुपए अपने किसान क्रेडिट कार्ड में जमा करने के लिए बैंक के कैशियर को सुपुर्द कर जमा की स्लिप प्राप्त की। लेकिन उनके खाते में यह राशि तीन वर्ष तक जमा नहीं हुई। जागरूक किसान रामस्वरूप माली ने जिला उपभोक्ता आयोग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा के विरुद्ध परिवाद दायर कर यह सारी जानकारी प्रमाण सहित प्रस्तुत की।

जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी होने के बाद विपक्षी बैंक द्वारा फरवरी 2021 में यह राशि परिवादी रामस्वरूप के अन्य खाते में जमा कर दी गई। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में राशि लेने के बावजूद उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते में जमा नहीं होना विपक्षी बैंक की सेवा में घोर कमी व गलती मानी। आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साहवा शाखा को आदेश दिया कि वह रामस्वरूप माली को उक्त राशि पर तीन वर्ष की अवधि का ब्याज और क्षतिपूर्ति स्वरूप 10,000 रुपए अदा करें। *(रा.प., 23.10.22)*

उपभोक्ता कर सकते हैं हेल्पलाइन पर वस्तु में खराबी या ज्यादा वसूली की शिकायत

किसी उत्पाद का कंपनी के वादे के अनुरूप नहीं होना, एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने जैसी स्थिति किसी उपभोक्ता के सामने आती है तो वह उचित मंच पर शिकायत दर्ज करवाकर 15 दिन में उसका समाधान पा सकता है। उपभोक्ता खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के आधीन उपभोक्ता मामले विभाग की हेल्पलाइन पर एक वर्ष के दौरान ऐसी 5684 शिकायतों में से 5295 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

इस तरह की शिकायतें हो रही दर्ज

- एमआरपी संबंधीः 15 से 20 प्रतिशत
- उत्पाद संबंधीः 20 से 25 प्रतिशत
- खाद्य सुरक्षा योजनाः 20 से 25 प्रतिशत
- जानकारी के अभाव मेंः 10 प्रतिशत

एक वर्ष में राज्य आयोग और जिला आयोग में 10404 शिकायतें दर्ज तथा 9 हजार सेज्यादा शिकायतों का समाधान 15 दिन में करने का दावां

विभाग का दावा है कि 15 दिन में उपभोक्ता की शिकायत का निवारण किया जाता है। हैल्पलाइन नंम्बर 18001806030 व व्हाट्सऐप नंबर 7230086030 पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। वहीं शिकायतों के समाधान की मॉनिटरिंग भी की जाती है।

यदि 15 दिन में समाधान नहीं हो तो मामला राज्य आयोग में हेल्पलाइन या व्हाट्सऐप पर दर्ज शिकायत के समाधान की प्रक्रिया के तहत विक्रेता या संबंधित को हेल्पलाइन मैनेजर की ओर से नोटिस दिया जाता है। फिर उपनिदेशक के जरिए नोटिस भेजा जाता है। 15 दिन में पीड़ित उपभोक्ता की शिकायत का समाधान नहीं होने पर शिकायत को राज्य आयोग भेजा जाता है। *(रा.प., 24.12.22)*

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.228 2821
फैक्सः 228 2485, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिगटन डी.सी. (यूएसए)